आर.एन.आई. पंजीयन क्र. 39596/82 (डाक पंजीयन MP/IDC/1462/2016-2019)

साप्ताहिक

मालव अँचल

वर्ष 47 अंक 52 (प्रति रविवार) इंदौर, 15 सितम्बर से 21 सितम्बर 2024 पृष्ठ-8 मूल्य 3 रुपये

स्वस्थ भारत और विकसित भारत के निर्माण के लिये आगे बढ़ें–मुर्मु

1692 करोड़ के उज्जैन-इन्दौर सिक्स-लेन रोड़ का किया भूमि-पूजन, प्रदेश में समग्र विकास के लिये मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं

इन्दौर। शहरी और ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में मप्र की अग्रणी भूमिकाराष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने कहा है कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और विकसित भारत के निर्माण के लिये सभी आगे बढ़ें। स्वच्छता ही देश को स्वस्थ और विकसित बना सकती है। देश का प्रत्येक व्यक्ति इस कार्य में सहयोग करे और सब मिलकर देश को विकसित राष्ट्र बनायें। मध्यप्रदेश ने शहरी और ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। मध्यप्रदेश के कई शहरों को सफाई के लिये श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है। इन्दौर निरन्तर 7वीं बार देश का स्वच्छतम शहर घोषित हुआ है। भोपाल स्वच्छतम राजधानी बनी है। राष्ट्रपति ने स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उनकी पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी।

राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु आज उज्जैन में सफाई मित्रों के सम्मान समारोह को सम्बोधित कर रही थीं। उन्होंने सफाई मित्रों श्रीमती रश्मि टांकले, श्रीमती किरण खोड़े, श्रीमती शोभा घावरी, श्रीमती अनिता चावरे और श्री गोपाल खरे का सम्मान भी किया। राष्ट्रपति ने 1692 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले उज्जैन-इन्दौर सिक्स-लेन मार्ग का भूमि-पूजन भी किया। प्रारम्भ में

राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु का राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया और उन्हें श्रीमहाकाल लोक की प्रतिकृति प्रदान की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा, प्रभारी मंत्री श्री गौतम टेटवाल, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट और नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी भी उपस्थित थे।

राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने कहा कि अवन्तिका बाबा महाकाल की पवित्र, दिव्य एवं पावन नगरी है। गुप्तकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग रहा है और उस समय उज्जैन भारत का महत्वपूर्ण नगर था। यहां संस्कृति और सभ्यता की प्राचीन परम्परा है। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने कहा कि आज से 2000 वर्ष पूर्व उज्जैन परिवहन व्यवस्था का उत्कृष्ट केन्द्र था। यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का केन्द्र भी था। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में उज्जयिनी की विशालता और भव्यता का अदभुत चित्रण किया है। देवलोक में जो महत्व अल्कापुरी नगरी का है, वही महत्व पृथ्वी पर उज्जैन नगरी का बताया गया है। मैं बाबा महाकाल, अवन्तिका नगरी और पवित्र शिप्रा नदी को प्रणाम करती हूँ। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने कहा कि उज्जैन एवं प्रदेश में समग्र विकास के अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। इसी क्रम में आज उज्जैन में उज्जैन-इन्दौर सिक्सलेन मार्ग का भूमि-पूजन किया गया है। यहां विक्रम उद्योगपुरी मेडिकल डिवाइसेस पार्क बनाया जा रहा है।

आतिशी मुख्यमंत्री के तौर पर 21 सितम्बर को शपथ लेंगी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने गुरुवार को पुष्टि की कि दिल्ली की मनोनीत मुख्यमंत्री आतिशी और उनका मंत्रिमंडल 21 सितंबर को पद की शपथ लेगा। सत्तारूढ़ दल ने शुरू में तय किया था कि केवल आतिशी ही शपथ लेंगी, हालांकि बाद में यह तय हुआ कि उनकी मंत्रिपरिषद भी शपथ लेगी। अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद आतिशी ने राष्ट्रीय राजधानी में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। इससे पहले आतिशी वित्त, शिक्षा और राजस्व जैसे 14 विभागों का प्रबंधन कर रही थीं और अरविंद केजरीवाल के कारावास के दौरान उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। कांग्रेस की शीला दीक्षित और बीजेपी की सुषमा स्वराज के बाद आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनेंगी।

'बुलडोजर न्याय' पर एक अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट की रोक

नई दिल्ली। बुलडोजर न्याय पर सुप्रीम रोक लग गई है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के पहियों पर ब्रेक लगाने वाला अंतरिम आदेश दिया। गैरकानूनी ध्वस्तीकरण पर चिंता जताते हुए कोर्ट ने इसे संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। कहा, अगर अवैध ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है तो वह संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध हैं। कोर्ट ने देशभर की अथारिटीज को आदेश दिया कि एक अक्टूबर तक कोर्ट की इजाजत के बगैर कोई संपत्ति नहीं ढहाई जाएगी, जिसमें किसी अपराध में आरोपित की संपत्ति भी शामिल है। मामले में एक अक्टूबर को फिर सुनवाई होगी। यह आदेश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने अपराध के आरोपितों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिए। हालांकि उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस तरह के अंतरिम आदेश का जोरदार विरोध किया। उनका कहना था कि कोर्ट के सामने यह धारणा पेश की जा रही है कि किसी अपराध में आरोपित समुदाय विशेष के लोगों की संपत्तियां ही ढहाई जा रही हैं, जबकि वह उदाहरण दे सकते हैं कि मध्य प्रदेश में हिंदुओं के घर भी ढहाए गए हैं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ऐसा एक भी उदाहरण पेश करें जिसमें कानून का पालन नहीं किया गया है। मेहता ने कहा कि किसी भी प्रभावित व्यक्ति ने याचिका दाखिल नहीं की है। हालांकि कोर्ट ने उनके विरोध को दरकिनार कर दिया और कहा कि एक सप्ताह तोड़फोड़ नहीं होगी तो क्या हो जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक संपत्ति जैसे सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइनों या जल निकायों आदि का अतिक्रमण तोड़े जाने पर यह रोक लागू नहीं होगी। तत्काल प्राथमिकता प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।

बिहार के सिंघम आईपीएस शिवदीप लांडे ने दिया इस्तीफा

पटना। बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी शिवदीप वामनराव लांडे ने गुरुवार को सेवा से इस्तीफा दे दिया। 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी को पूर्णिया रेंज के महानिरीक्षक (आईजी) के रूप में तैनात किया गया था। उन्हें हाल ही में तिरहुत रेंज (मुजफ्फरपुर) से पूर्णिया रेंज में स्थानांतरित किया गया था। एक ईमानदार और धाकड़ आधिकारी माने जाने वाले लांडे पिछले दो महीनों में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) से इस्तीफा देने वाले दूसरे अधिकारी हैं। उन्हें बिहार का सिंघम भी कहा जाता है। वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी बेहद भरोसेमंद थे। लांडे ने आईपीएस से अपने इस्तीफे की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की। अपने पोस्ट में उन्होंने कहा कि करीब 18 साल तक राज्य की सेवा की और हमेशा अपनी नौकरी को प्राथमिकता दी।

संपादकीय

सारी दुनिया,इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों से भयभीत

सारी दुनिया के देशों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और संचार व्यवस्था को लेकर एक अज्ञात भय समा गया है। लेबनान में जिस तरह से हजारों पेजरों,इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, वॉयरलैस आधारित वॉकी-टॉकी इत्यादि के माध्यम से सामूहिक विस्फोट किए गए हैं। इन विस्फोटों में हजारों लोगों घायल हुए हैं। सैकड़ो लोग मौत का शिकार हो गए हैं। कई स्थानों पर मोबाइल डिवाइस पर भी इसी तरह के धमाके किए गए हैं। सेना के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में विस्फोट अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों, नर्सों के पेजर और मोबाइल फोन पर भी हुए हैं। जिसके बड़ी संख्या में डॉक्टर नर्स और मरीज घायल हुए हैं। उसके कारण अब लोगों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और संचार माध्यमों के उपयोग को लेकर भय फैल गया है। पिछले तीन दशक में दुनिया के सभी देशों में इंटरनेट का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है। पिछले दो दशक में ऑनलाइन सेवाओं का जाल बिछाया गया है। कम्युनिकेशन के सभी संसाधन इंटरनेट के माध्यम से आपस में जुड़ गए हैं। टेलीविजन भी अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंटरनेट के माध्यम से सारी दुनिया में सेवाएं दे रहे हैं। मोबाइल फोन गरीब से गरीब के व्यक्ति के पास उपलब्ध है। घरों में जो टीवी लगी हैं। वह भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं इंटरनेट के माध्यम से कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहे हैं। सभी माध्यमों में कुछ ही लोगों का एकाधिकार है। विशेष रूप से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तैयार करने वाली संस्थाओं कुछ ही कंपनियों पर एकाधिकार है। इस तकनीकी पर घुसपैठ करने वालों की संख्या भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। हैकिंग सिस्टम के माध्यम से हैकर तकनीकी को ध्वस्त करते हुए कमाई के नए-नए आयाम खोजने में लगे हैं। युद्ध लड़ने के जो नए तरीके अब विकसित हो रहे हैं। वह बहुत विनाशकारी हैं। पहले जो युद्ध हुए हैं, उसमें उतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जितना बड़ा नुकसान अब सारी दुनिया के देशों को हो सकता है। पहले रासायनिक हथियारों का एक भय था। अब जिस तरह से व्यक्ति को लक्ष्य करके हमले किए जा रहे हैं। उसने सारी दुनिया को हैरानी और परेशानी में डाल दिया है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में विस्फोट की आशंका को देखते हुए, सभी देशों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की विश्वसनीयता और उपयोग को लेकर बड़ा संशय पैदा हो गया है। सारी दुनिया एक ही नेटवर्क से जुड़ी हुई है। सभी संचार माध्यम आपस में जुड़े हुए होने के कारण कम समय में सारी दुनिया के देशों को लक्ष्य किया जा सकता है। यह आशंका अब बलवती होने लगी है। पिछले एक दशक में जिस तरह से इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन नेटवर्किंग से दुनिया की 70 फ़ीसदी से ज्यादा आबादी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नेटवर्क के माध्यम से जुड़ चुके है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग युद्ध में हथियार के रूप में किया गया है। उसके कारण लोगों के बीच में यह चर्चा होने लगी है। पेजर तकनीकी जो वायरलेस के माध्यम से एक सीमित क्षेत्र में वन वे कम्युनिकेशन के रूप में काम करती है। यदि वह सुरक्षित नहीं है। ऐसी स्थिति में लोगों की सुरक्षा किस तरह संभव होगी, यह समझना मुश्किल हो गया है। भारत सहित दुनिया के अन्य देशों के संचार माध्यम इंटरनेट से संचालित हो रहे हैं। घरों की टीवी में जो प्रसारण आ रहा है। वह भी इंटरनेट के माध्यम से आ रहा है। एंड्राइड तकनीकी के टेलीविजन दुनिया भर के अरबों टेलीविजन और मोबाइल एक ही सिस्टम से संचालित हो रहे हैं। सारे सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कब इस सिस्टम के अंदर कौन घुसकर क्या करके निकल जाएगा कहना मुश्किल है।

'एक देश एक चुनाव' अमृतकाल की अमृत उपलब्धि बने

ललित गर्ग

नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने 'एक देश एक चुनाव' के अपने चुनौतीपूर्ण संकल्प को लागू करने की बात कहकर राजनीतिक चर्चा को गरमा दिया है। भारत के लोकतंत्र की मजबूती एवं चुनावी प्रक्रिया को अधिक प्रासंगिक एवं कम खर्चीला बनाने के लिये 'एक देश एक चुनाव' पर चर्चा होती रही है। इसको लेकर भाजपा जिस तरह बेझिझक होकर तेजी से आगे बढ़ रही है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा कि केंद्र को सहयोगी दलों का पूरा समर्थन मिल रहा। दो बड़े दलों में से एक जेडीयू ने मोदी के 'एक देश एक चुनाव' वाले इरादे पर सहमति जता दी है। कहा गया कि राजग सरकार अपने वर्तमान कार्यकाल के भीतर इस महत्वपूर्ण चुनाव सुधार को लागू कराने को लेकर आशावादी है और उसके इस आशावाद में देश को एक नई दिशा मिल सकेगी। भारत की वर्तमान चुनावी प्रणाली में निहित कई चुनौतियों का समाधान करने के लिए 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा एक संभावित समाधान के रूप में उभरी है। शासन के सभी स्तरों- पंचायत, नगरपालिका, राज्य और राष्ट्रीय- में एक साथ चुनाव कराने से लागत खर्च -प्रभावशीलता और प्रशासनिक दक्षता से लेकर बेहतर शासन और नीति निरंतरता तक कई लाभ मिल सकते हैं। यह नये भारत, सशक्त भारत एवं विकसित भारत के संकल्प को आकार देने का मुख्य आधार बन सकता है एवं आजादी के अमृतकाल की एक अमृत उपलब्धि बनकर सामने आ सकता है।

भले ही स्पष्ट बहुमत के अभाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग की तीसरी पारी में बदलावकारी फैसले लेना उतना सहज नहीं रह गया है, जितना पहली-दूसरी पारी में नजर आता था। लेकिन भाजपा की सरकार इतनी भी कमजोर नहीं है कि अपने चुनावी वायदों एवं विकासमूलक कार्ययोजनाओं को लागू न कर सके। नरेन्द्र मोदी जैसा साहसी एवं करिश्माई नेतृत्व है तो उसके द्वारा देशहित की योजनाओं में आने वाले अवरोध वह दूर कर ही लेंगे। एक दशक की विकासमूलक कार्यशैली के बाद अब भी भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर अपनी योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने में जुटी है। भले ही भाजपा-सरकार कई मुद्दों पर यू टर्न लेते हुए भी नजर आई। बहरहाल, लोकसभा में पहले के मुकाबले कमजोर स्थिति होने के बावजूद खुद को साहसिक निर्णय लेने वाली पार्टी के रूप में एक बार फिर अपने एक मुख्य एजेंडे 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को आकार देने के लिये तत्पर हो गयी है। इसके लिए सरकार ने पक्ष-विपक्ष के सभी नेताओं से एक साथ आने का अनुरोध किया था। निस्संदेह, एक राष्ट्र, एक चुनाव के लिये भाजपा द्वारा नई पहल किए जाने के निहितार्थ राजनीति से ज्यादा राष्ट्रहित में है।

निश्चिय ही 'एक देश एक चुनाव' की योजना को लागू करना राजग के लिये बड़ी चुनौती होगी क्योंकि इस बार विपक्ष पहले के मुकाबले मजबूत भी है और एकजुट भी है। इसमें दो राय नहीं कि यह बात तार्किक है कि एक राष्ट्र, एक चुनाव का प्रयास शासन में सुनिश्चितता लाएगा। वहीं बार-बार के चुनाव खर्चीले होते हैं। दूसरे राज्य-दर-राज्य लंबी आचार संहिता लागू होने से विकास कार्य भी बाधित होते हैं। साथ ही साथ शासन-प्रशासन व सुरक्षा बलों की ऊर्जा के क्षय के अलावा जनशक्ति का अनावश्यक व्यय होता है। विगत लोकसभा चुनावों में कुल सरकारी खर्च 6600 करोड़ रुपये आया था जो भारत जैसे विविधतापूर्ण विशाल देश को देखते हुए भले ही जायज कहा जाये, लेकिन बार-बार होने वाले चुनावों से होने वाले ऐसे भारी-भरकम खर्चे देश की अर्थ-व्यवस्था पर बोझ तो डालते ही है। भारत में भ्रष्टाचार की जड़ भी महंगी होती चुनाव व्यवस्था है क्योंकि जब करोड़ों रुपये खर्च करके कोई विधानसभा या लोकसभा का प्रत्याशी जनप्रतिनिधि बनेगा तो वह विजयी होने के बाद सबसे पहले अपने भारी खर्च की भरपाई करने की कोशिश करेगा। अतः असल में बात सम्पूर्ण चुनावी व्यवस्था के सुधार की होनी चाहिए। मगर इसकी बात करने पर सभी राजनैतिक दलों में एक सन्नाटा पसर जाता है। लेकिन पक्ष एवं विपक्ष को अपने राजनीतिक हितों की बजाय देशहित को सामने रखकर इस मुद्दे पर आम सहमति बनानी चाहिए। पारदर्शी व निष्पक्ष चुनाव के लिये एक साथ चुनावी मशीनरी तथा सुरक्षा बलों की उपलब्धता के यक्ष प्रश्न को भी सामने रखकर इस पर सकारात्मक रूख अपनाना चाहिए और इसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, भारत हमेशा से राजनीतिक विचारधाराओं, विविध संस्कृतियों और विशाल आबादी का मिश्रण रहा है। हर गुजरते चुनाव चक्र के साथ, राष्ट्र लोकतांत्रिक उत्साह का महाकुंभ देखता है, जहाँ लाखों लोग अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करते हैं और अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। हालाँकि, इस जीवंत लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बीच, विभिन्न स्तरों-स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय-पर चुनावों के समन्वय को लेकर बहस ने हाल के वर्षों में काफी जोर पकड़ा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने एक दशक के शासन एवं पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से किए गए अपने संबोधन में 'एक देश, एक चुनाव' की जोरदार वकालत की थी और कहा था कि बार-बार चुनाव होने से देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो रही है। उन्होंने राजनीतिक दलों से लाल किले से और राष्ट्रीय तिरंगे को साक्षी मानकर राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित करने का आग्रह किया था। हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा द्वारा जारी चुनाव घोषणापत्र में उसने 'एक देश, एक चुनाव' को प्रमुख वादों के रूप में शामिल किया था।

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने इस साल मार्च में पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की। समिति ने राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों के साथ परामर्श किया और संभावित अनुशंसाओं के साथ आम लोगो एवं न्यायविदों के विचार आमंत्रित किये। समिति ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाने की भी सिफारिश की। इसके अलावा, विधि आयोग भी 2029 से एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश कर सकता है। असल में बात सम्पूर्ण चुनावी व्यवस्था के सुधार की होनी चाहिए। मगर इसकी बात करते हुए सभी राजनैतिक दलों के सामने निजी हित एवं चुनाव जीतने का गणित सामने आ जाता है। भारत की असली विडम्बना यही है। जब भी सरकारी खर्चे से चुनाव कराने की बात होती है तो इस राह को अव्यावहारिक बता दिया जाता है। जबकि जर्मनी जैसे लोकतन्त्र में यह प्रणाली सफलतापूर्वक काम कर रही है। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव एक साथ प्रत्येक पाँच वर्ष पर आयोजित किये जाते हैं, जबकि नगर निकाय चुनाव प्रत्येक दो वर्ष पर आयोजित किये जाते हैं। स्वीडन में राष्ट्रीय विधानमंडल, प्रांतीय विधानमंडल/काउंटी कौंसिल और स्थानीय निकायों/नगर निकाय सभाओं के चुनाव एक निश्चित तिथि, यानी हर चौथे वर्ष सितंबर के दूसरे रविवार को आयोजित किये जाते हैं। ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद और उसके कार्यकाल को स्थिरता एवं पूर्वानुमेयता की भावना प्रदान करने के लिये निश्चित अवधि संसद अधिनियम, 2011 पारित किया गया था। इसमें प्रावधान किया गया कि प्रथम चुनाव 7 मई 2015 को और उसके बाद हर पाँचवें वर्ष मई माह के पहले गुरुवार को आयोजित किया जाएगा।

जब दुनिया के अनेक देशों में 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' की परम्परा सफलतापूर्वक संचालित हो रही है तो भारत में इसे लागू करने में इतने किन्तु-परन्तु क्यों है? देश में इसे लागू करने से सरकार कुछ-कुछ समय बाद चुनावी मोड में रहने के बजाय शासन यानी विकास योजना पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकती है। इससे समय एवं संसाधनों की भी बचत होगी। एक साथ चुनाव कराने से मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के लिए एक साथ कई मत डालना आसान हो जाएगा। इन सब स्थितियों के साथ-साथ एक साथ चुनाव कराये जाने पर क्षेत्रीय पार्टियों को होने वाले नुकसान एवं अन्य स्थितियों पर भी ध्यान देना होगा। क्योंकि एक आदर्श एवं सशक्त लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों के लिये समान अवसर उपलब्ध होना भी जरूरी है।

राहुल गांधी द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर ज्ञापन सौंपा

इन्दौर। *भारतीय जनता पार्टी इंदौर नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे ने राहुल गांधी द्वारा अमेरिका के वर्जिनीया में भारत के सिख समुदाय को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरुद्ध इंदौर कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर कमिश्नर राकेश गुप्ता को ज्ञापन सौंपा।*

गौरव रणदिवे के द्वारा ज्ञापन में कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सिख समाज व अन्य कई धर्म समुदायों के नागरिक एवं प्रतिनिधि मुझ से मिले चर्चा में उनके द्वारा बताया गया कि विगत 10 सितम्बर,2024 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता एवं लोकसभा के नेताप्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा एक सभा में कहा कि भारत में असली लड़ाई सिखों को पगड़ी पहनने-कड़ा पहनने की है भारत में कुछ ही धर्मो को छोड़ कर अन्य धर्मो के साथ भी अपनी परम्पराएं निभाने, धार्मिक परिवेश अपनाने एवं धार्मिक आस्था को निभाने की लड़ाई चल रही है, जिस संबंध में राहुल गांधी द्वारा वर्जिनीया में आमजन के बीच दिये गये कथन का वीडियों व पेपर न्यूज दिखाई गई, व व्यक्त किया गया जिसे देख, सुन व पड़कर उनके मन में भारी क्षोभ हुआ।

जब मैंने व कार्यालय पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा उक्त वीडियों देखा व सुना तो मेरे व उनके मन में भी भारी आक्रोश उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता एवं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष एक जिम्मेदार लोकतंत्र के सदस्य होकर एक संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति है। राहुल गांधी के द्वारा दिया गया कथन सार्वजनिक रूप से ना सिर्फ धर्म एवं मूलवंश के आधार पर भारत में विभिन्न धर्म एवं समूह के बीच सार्वजनिक शत्रुता को बढ़ावा देने एवं भारत के सद्भाव एवं साम्प्रदायिकता पर प्रतिकुल प्रभाव डालने का कार्य है, बल्कि इस प्रकार राहुल गांधी के द्वारा जो उपरोक्त कृत्य किया गया वह विभिन्न समुदायों के बीच में सदभाव को बिगाड़कर राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकुल प्रभाव डालने वाला होकर सिख समुदाय अन्य धर्म वर्ग के लोगों के धार्मिक विश्वास का जानबुझ कर दुर्भावनापूर्ण तरीके से ठेस पहुंचाते हुए विभिन्न वर्गो की जानबूझ कर शब्दों से ठेस पहुंचाने वाला कृत्य है। जो वर्गो एवं धर्मो के बीच घृणा व दुर्भावना भी पैदा करता है जो कि स्पष्ट रूप से राहुल गांधी की कुत्सित मानसिकता को भी प्रकट करता है किस प्रकार राहुल गांधी योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न धर्मो, जाति, समुदायों के व्यक्तियों में वैमन्स्य बढ़ाकर देश में ना सिर्फ अराजकता का माहौल खड़ा करना चाहते है, बल्कि विदेशों में भी भारत की छवि का मिथ्या प्रतिरूपण कर वैश्विक आघात पहुंचाना चाहते है।इस प्रकार राहुल गांधी जो कि एक संवैधानिक पद पर होकर नेताप्रतिपक्ष व एक लोकसभा सदस्य के रूप में जिम्मेदार नागरिक भी है, का इस प्रकार धर्म, जाति, भाषा के आधार पर संबोधन करते हुए वैमन्स्य पैदा करना, देश में किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वास का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को जानबुझ कर और दुर्भावना तरीके के ठेस पहुंचाकर देश की एकता, अखण्डता व साम्प्रदायिकता को खंडित कर देश में अराजकता फैलाकर देश की शांति भंग करना गंभीरतम अपराध की श्रेणी में आता है। इस प्रकार के कृत्यों को विधि अनुसार तत्काल रोक लगाना आवश्यक है।

नगर निगम ने कर्बला मैदान का कब्जा लिया, बोर्ड लगाया

निगम ने हाई कोर्ट में कैविएट भी दायर कर दी

इंदौर। वक्फ बोर्ड और कबला कमेटी के खिलाफ जिला कोर्ट में मिली जीत के बाद नगर निगम ने बुधवार को कर्बला मैदान का औपचारिक कब्जा ले लिया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव खुद निगमायुक्त शिवम वर्मा के साथ कर्बला मैदान पहुंचे और कब्जा लेने की औपचारिकता पूरी की। निगम ने यहां अपने स्वामित्व का बोर्ड भी लगा ड़ दिया है। इस मैदान को दिल्ली के प्रगति मैदान की तर्ज पर विकसित करने की योजना है। बुधवार को ही. निगम ने इस मामले में हाई कोर्ट में कैविएट भी दायर कर दी ताकि किसी भी तरह का अंतरिम आदेश सुनाने से पहले उसका पक्ष भी सुना जाए।

कर्बला मैदान को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में हाल ही में निगम को बड़ी जीत मिली

है। जिला कोर्ट ने इस मामले में निगम की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकारते हुए माना है कि कर्बला मैदान की 6.70 एकड़ जमीन निगम के स्वामित्व की है और इस पर कर्बला मैदान कमेटी या वक्फ बोर्ड का कोई स्वामित्व नहीं है। इसके बाद बुधवार सुबह महापौर और निगमायुक्त निगम की टीम के साथ कर्बला मैदान पहुंचे। निगम ने यहां स्वामित्व संबंधी बोर्ड लगाते हुए जमीन का औपचारिक कब्जा ले लिया। निगम द्वारा लगाए गए बोर्ड पर कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया गया है।

वक्फ में रजिस्टर्ड थी, इसे कोर्ट ने माना गलत -महापौर ने कहा कि इस मैदान और 7 इसके आसपास अवैध कब्जे की शिकायत भी मिली है। हम इसकी जांच करेंगे और अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कोर्ट के फैसले को लेकर उन्होंने कहा कि यह जमीन वक्फ में रजिस्टर्ड थी और कोर्ट ने इस रजिस्ट्रेशन को गलत मानते हुए निगम के पक्ष में फैसला सुनाया है। यह हमारे लिए ऐतिहासिक महत्व का फैसला है। इस जमीन का रजक समाज भी लंबे समय से उपयोग करता रहा है। योजना तैयार करते वक्त हम इस बात को भी ध्यान में रखेंगे।

हुकमचंद मिल की झांकी को मिला प्रथम स्थान

अखाड़ों में चंद्रपाल उस्ताद एवं छोगालाल उस्ताद व्यायाम शाला को मिला प्रथम स्थान

इंदौर। इंदौर की गौरवशाली परम्परा के रूप में अनन्त चतुर्दशी चल समारोह पूर्ण श्रद्धा, आस्था एवं अपार उत्साह-उमंग और व्यापक जनभागीदारी के साथ सम्पन्न हुआ। नागरिकों ने इस उत्सव के प्रति अपनी सक्रिय सहभागिता निभाते हुये शहर की परम्परा को अपार उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ाया। रातभर जोश और उल्लास के साथ चल समारोह में निकली नयनाभिराम झाँकियों और अखाड़ों के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने हजारों लोगों का मन मोह लिया। जिला प्रशासन द्वारा गठित झाँकी तथा अखाड़ा निर्णायक समितियों द्वारा पुरस्कार के लिये सर्वसम्मति से श्रेष्ठ झाँकियों और अखाड़ों का चयन किया गया। झांकी में हुकमचंद मिल की श्रीकृष्ण और इंद्र देवता का युद्ध झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसी तरह अखाड़ों में चंद्रपाल उस्ताद व्यायामशाला और छोगालाल उस्ताद व्यायामशाला को प्रथम स्थान मिला। इसी तरह महिला वर्ग का विशेष पुरस्कार रामनाथ गुरू शस्त्र कला व्यायामशाला को दिया गया। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने चल समारोह सुचारू रूप से सम्पन्न होने पर इंदौर के नागरिकों, व्यवस्थाओं से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों, झाँकी आयोजकों और अखाड़ों के सदस्यों तथा मीडियाकर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया है।

प्रशासन ने होटल श्रीमाया सहित 7 बिल्डिंग के बेसमेंट किए सील

इंदौर। शहर के ट्रैफिक को सुधारने की प्रशासन की मुहिम ने गति पकड़ ली है। अब पार्किंग के बजाए व्यवसायिक उपयोग करने वाली बिल्डिंगों के बेसमेंट सील किए जा रहे हैं। मंगलवार को सात बिल्डिंगों पर कार्रवाई की गई, जिसमें नामी होटल श्रीमाया भी शामिल है। बेसमेंट में लांड्री व स्टोर संचालित किए जा रहे थे। मंगलवार को जूनी इंदौर एसडीएम घनश्याम धनगर के नेतृत्व में नगर निगम और पुलिस का अमला सपना-संगीता रोड पहुंचा। यहां तीन बिल्डिंगों के बेसमेंट को सील किया गया। बाद में बंगाली चौराहे के समीप दो बिल्डिंग के बेसमेंट सील किए। फिर अमला एबी रोड स्थित होटल श्रीमाया पहुंचा, जहां बेसमेंट पर पार्किंग के बजाए लांड्री व स्टोर संचालित किया जा रहा था। यहां आने वाले अपनी कार को बीआरटीएस पर पार्क करते हैं। इसलिए प्रशासन ने बेसमेंट सील कर दिया। इसके अलावा चंद्रलोक चौराहे पर बेसमेंट में संचालित हो रही जूम्बा डांस क्लास को भी सील किया है। कार्रवाई के दौरान बचने के लिए कुछ लोगों ने राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन अफसरों ने उन्हें साफ कर दिया कि कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी। पूर्व में भी पर्याप्त समय दिया गया था।

यहां पर की गई कार्रवाई- प्रिंस प्लाजा (सपना संगीता रोड) संजरी मेडिकल स्टोर, राधा स्वामी मेडिकल स्टोर डॉ. अश्विन जैन क्लिनिक, डॉल्फिन रेस्टोरेंट, सत्यगीता अपार्टमेंट (सपना संगीता रोड), रासलीला साड़ी, भारत प्लायवुड, सेंटर पाइंट (सपना संगीता रोड),प्रियांस सेल्स स्टेचिंग पाइंट, शिवांग इंटरप्राइजेस श्री बिल्डिंग मटेरियल, छह दुकान बिना नाम की, स्नेहा रीजेंसी कनाडिया रोड, संस्कृति अपार्टमेंट कनाडिया रोड, होटल श्रीमाया एबी रोड, लांड्री व स्टोर, संतोषी हाइट्स चंद्रलोक चौराहा खजराना स्टेट टीक वंडू एकेडमी बेसमेंट।

कमजोर परफॉर्मेंस से छिन रही ब्यूरोक्रेट्स की कुर्सी

डॉ. मोहन सरकार को बर्दास्त नहीं नाफरमान अफसर

भोपाल। सुशासन पर जोर दे रहे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का सबसे अधिक फोकस अफसरों की कार्यप्रणाली सुधार पर रहा है। अपने 9 माह के शासनकाल में मुख्यमंत्री ने नाफरमान अफसरों को हटाने में तनिक भी देर नहीं की है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मोहन यादव सरकार ने 9 महीने में 32 कलेक्टर बदले हैं। वहीं तकरीबन हर दिन एक आईएएस का तबादला या प्रभार बदला है। दरअसल, कमजोर परफॉर्मेंस और संवेदनशील विषयों पर असंवेदनशीलता बरतने वाले आईएएस अफसर मोहन सरकार के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। सरकार ने 9 माह के कार्यकाल में ऐसे 21 से अधिक अफसरों को इन्हीं कारणों से हटाया है।

प्रदेश में डॉ. मोहन यादव की सरकार बनने के बाद कलेक्टरों पर सबसे अधिक नकेल कसी गई। खराब फरफॉर्मेंस पर कलेक्टरों को तत्काल बदल दिया गया। जो अफसर सरकार वर्किंग स्टाइल के अनुसार काम करने में विफल रहे हैं और परफॉर्मेंस पर फिट नहीं बैठ रहे थे, जो संवेदनशील विषयों पर कार्रवाई में पीछे रह गए थे उन्हें बदलने में देर नहीं की गई है। कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें इसी सरकार ने जिलों में कलेक्टर जैसी बड़ी भूमिका दी थी, लेकिन 5-8 माह में ही हटा दिए। कुछ को संबंधित पदों पर काम करते हुए तीन साल की आदर्श अवधि पूरी होने के पहले हटाया। सूत्र

बताते हैं, कुछ और भी ऐसे अफसर हैं, जिनके काम में सुधार नहीं हुआ तो हटाए जा सकते हैं। यूं तो सरकार के लिए राज्य से जुड़े हर विषय संवेदनशील हैं। इसी अनुसार काम भी किए जा रहे हैं लेकिन विकसित भारत, विकसित मप्र, आर्थिक मजबूती, पर्यटन, संस्कृति, रोजगार के अवसर, महिला सुरक्षा, पर्यावरण व गो संरक्षण, खेती किसान व किसानों से जुड़े विषय प्रमुख प्राथमिकताओं में हैं।

इसलिए हटाए गए ये अफसर- लोकसभा चुनाव के पहले मार्च में बुद्धेश कुमार वैद्य विदिशा कलेक्टर बनाए गए। पांच माह में ही अगस्त में हटाए गए। तब चर्चा थी कि क्षेत्र के धर्मस्थल बीजामंडल को व पुरातात्विक विभाग के हवाले से मस्जिद का हिस्सा बताया। अभी गृह उपसचिव हैं। क्षितिज सिंघल जनवरी 2023. में सिवनी कलेक्टर बने। जुलाई 2024 में हटाए गए। वजह रही, गोवंश के कटे सिर मिलना। ऐसी 4 घटना दो दिन में हुई। यह तब हुआ, जब सरकार गोवंश संरक्षण पर जोर दे रही थी। मध्य क्षेत्र बिजली कंपनी के एमडी हैं। स्वतंत्र कुमार सिंह फरवरी 2024 में आयुक्त, वाणिज्यिक कर इंदौर बने। जुलाई में हटा दिए गए। वे पहले लंबे समय से लूपलाइन में थे। सूत्र बताते हैं, इंदौर में उन्हें लेकर शिकायतें आई थीं। अभी स्वतंत्र बीजीटीआर के डायरेक्टर हैं। पिता इकबाल सिंह बैंस के मुख्य सचिव रहते अमनबीर को फरवरी 2021 में बैतूल कलेक्टर बनाया। दिसंबर 2023 में गुना कलेक्टर बनाया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की फटकार से सुर्खियों में आए, मार्च 2024 में हटा दिए गए। सलोनी सिडाना को विधानसभा चुनाव के पहले अप्रेल 2023 में मंडला कलेक्टर बनाया। इस साल अगस्त में हटाया। अमूमन 3 साल बाद कलेक्टर बदले जाते हैं। बताते हैं, जनप्रतिनिधि उनके काम से नाखुश थे। वे भारतीय चिकित्सा प्रणाली की आयुक्त हैं। पीएस पर्यावरण गुलशन बामरा को सडक़ों से मवेशी नहीं हटाए जाने के कारण हटाया गया। दरअसल, मवेशी सडक़ों पर हैं, सीएम बार-बार कह चुके कि मवेशियों को हटाने और उनके लिए इंतजाम करने की जरूरत है। पर संतोषजनक काम नहीं हुआ। ऐसे में उनसे जिम्मेदारी वापस ले ली। बामरा के पास नवंबर 2022 से यह जिम्मेदारी थी। संजीव कुमार झा को अप्रैल 2024 में चंबल संभाग की जिम्मेदारी दी थी। यह जिम्मेदारी उनसे बेहद कम कम समय में ही वापस ले ली गई। अब राजस्व बोर्ड के सदस्य हैं। चर्चा थी कामकाज से जनप्रतिनिधि नाखुश हैं।

तरुण भटनागर को 15 मार्च को मोहन सरकार ने शहडोल कलेक्टर बनाकर भेजा और पांच माह में ही वापस बुला लिया। तब चर्चा चली कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय में कमी रही। माफिया हावी रहे। दीपक आर्य को इसलिए हटाया गया कि सागर के शाहपुर में भवन की दीवार ढहने से 9 बच्चों की मौत हुई थी। बारिश में सीएम ने सतर्क रहने और जर्जर भवनों, पुल-पुलियाओं की निगरानी के निर्देश दिए थे। इस हादसे के बाद उन्हें हटाया गया। दिनेश जैन को विधानसभा चुनाव से पहले अप्रेल 2023 में नीमच कलेक्टर बनाया। वे डेढ़ साल भी पूरा नहीं कर सके और अगस्त 2024 में हटा दिए गए। समन्वय में कमी की चर्चाओं ने जोर पकड़ा था। भास्कर लक्ष्यकार को विधानसभा चुनाव 2023 के पहले अक्टूबर में रतलाम कलेक्टर बनाया। लोकसभा चुनाव के पहले मार्च 2024 में हटा दिया। महज 6 माह में हटाए जाने के पीछे कई तरह की चर्चा चली। सचिन सिन्हा प्रमुख सचिव श्रम थे। श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल विभागीय कुछ कामकाज से संतुष्ट नहीं थे, हटाए गए। हालांकि यह चर्चा तक ही है. वे अप्रेल 2021 से ही पद पर थे, इसलिए भी उन्हें हटाया गया।

9 महीने में बदले 32 कलेक्टर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा प्रशासन को चुस्त-दुरूस्त बनाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत विधानसभा चुनाव के पहले जिलों में पदस्थ किए गए कलेक्टरों में से अब तक 32 कलेक्टर बदले जा चुके हैं। जो कलेक्टर भाजपा की नई सरकार बनने के बाद नहीं बदले हैं, उनमें धार, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, आगर मालवा, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, भिंड, रीवा, सतना, मऊगंज, मैहर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सीहोर, रायसेन और पांढुर्णा शामिल हैं। शहडोल और विदिशा कलेक्टरों की पोस्टिंग और हटाने की कार्यवाही जल्दी हुई है।

प्रदेश में औद्योगिकरण के विस्तार में सहायक हैं इन्वेस्टर समिट - डॉ. यादव

भोपाल। *मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश, सभी क्षेत्रों में विकास के पथ पर अग्रसर है। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन निरंतर जारी है। हमारा प्रयास है कि देश-विदेश के निवेशक और उद्योगपति मध्यप्रदेश में निवेश करें और औद्योगिक गतिविधियों का संचालन करें। इससे प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे।*

देश के विभिन्न भागों में हो रही इन्वेस्टर समिट से उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद, उनकी समस्याओं के समाधान और औद्योगिक गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी उनसे साझा करने का अवसर मिलता है। यह परस्पर संवाद, आपसी विश्वास-सुरक्षा और भविष्य की संभावनाओं का आधार बनता है। अब तक हुई इन्वेस्टर समिट का प्रदेश को बड़े पैमाने पर लाभ मिला है। इसी क्रम में बेंगलुरु और मुंबई

के बाद अब कोलकाता में रोड शो अन्तर्गत इन्टरेक्टिव सेशन में निवेशकों से रू-ब-रू चर्चा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश में असीमित निवेश के अवसरों पर कोलकाता में आयोजित सत्र में सहभागिता के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री निवास में मीडिया को दिए संदेश में यह बात कही।

27 सितम्बर को सागर में होगी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव-मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार लघु उद्योग, मध्यम श्रेणी के उद्योग, फूड इंडस्ट्री, आईटी पार्क के माध्यम से युवाओं, महिलाओं सहित सभी के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से अभियान के रूप में गतिविधियां संचालित कर रही है। क्षेत्रीय स्तर पर जारी इन्वेस्टर समिट के आगामी क्रम में 27 सितंबर को सागर में समिट का आयोजन होगा। प्रदेश में कुटीर उद्योग के रूप में बीड़ी और अगरबत्ती उद्योग घर-घर में होता था, सागर क्षेत्र की तो यह विशेष पहचान था। वर्तमान में सागर क्षेत्र में खनिज सेक्टर भी प्रमुख गतिविधि के रूप में उभरा है। इससे पहले जबलपुर और ग्वालियर में समिट आयोजित हो चुके हैं। क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित समिट के माध्यम से निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को क्षेत्रीय स्तर तक ले जाने में मदद मिली है। प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों के भूमि-पूजन और लोकार्पण का क्रम जारी है। साथ ही इन्वेस्टर समिट के माध्यम से हम उद्योगपतियों और निवेशकों को प्रदेश में आने के लिए आमंत्रित और प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। इन प्रयासों का ही परिणाम है कि मध्यप्रदेश में शिक्षा, चिकित्सा सहित सभी औद्योगिक क्षेत्र में निवेश बढ़ा है और उद्योगपति प्रदेश में निवेश के लिए उत्साह के साथ इच्छुक हैं।

औद्योगिक गतिविधियों के विस्तारीकरण और विविधिकरण के लिए प्रदेश में पर्याप्त अवसर उपलब्ध-मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में जो उद्योगपति पहले से सक्रिय हैं, उनकी गतिविधियों के विस्तारीकरण और विविधिकरण के लिए भी प्रदेश में अवसर उपलब्ध हैं। राज्य सरकार सहयोगात्मक रूख के साथ सकारात्मक वातावरण निर्मित करते हुए शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, खनन, वनीकरण एवं पर्यटन सहित सभी क्षेत्रों में गतिविधियों के विस्तार और विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

कूनो और गांधी सागर के बीच बनेगा सबसे बड़ा चीता संरक्षण परिसर

भोपाल। भारत का लक्ष्य अगले 25 साल के भीतर मप्र और राजस्थान के कूनो-गांधी सागर परिक्षेत्र में एक अंतर-राज्यीय चीता संरक्षण परिसर का निर्माण करना है। इसमें मध्य प्रदेश के 8, राजस्थान के 7 और यूपी के 2 जिलों को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही 5 साल के भीतर कूनो से गांधी सागर के बीच चीता कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू किया जाएगा। प्रोजेक्ट चीता की 2023-24 की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

प्रोजेक्ट चीता के दो साल पूरे होने पर 17 सितंबर को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वर्ष के अंत तक गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में चीतों का एक नया ग्रुप लाए जाने की संभावना है और उन्हें अगले पांच साल तक खुले माहौल में छोड़ा जाएगा। गांधी सागर में चीता लाने की कार्य योजना के अनुसार, पहले चरण में 5 से 8 चीतों को 64 वर्ग किलोमीटर के शिकारी-रोधी बाड़ वाले क्षेत्र में छोड़ा जाएगा, जिसमें प्रजनन पर ध्यान दिया जाएगा। अब इन देशों से भारत आएंगे चीते !-रिपोर्ट में कहा गया है कि मप्र और राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा पर ये दोनों स्थल एक-दूसरे से सटे हुए हैं। इसमें कहा गया है कि प्रोजेक्ट चीता के तहत देश का लक्ष्य अगले 25 वर्ष के भीतर मप्र और राजस्थान के कूनो-गांधी सागर परिक्षेत्र में एक अंतर-राज्यीय चीता संरक्षण परिसर का निर्माण करना है। यह कूनो-गांधी सागर परिक्षेत्र मध्य प्रदेश के श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, गुना, अशोकनगर, मंदसौर और नीमच जिलों और राजस्थान के बारां, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, झालावाड़, बूंदी और चित्तौडग़ढ़ जिलों में स्थित है। रिपोर्ट के अनुसार, इस क्षेत्र से सटे मप्र के भिंड और दतिया जिले, राजस्थान के धौलपुर तथा उत्तर प्रदेश के ललितपुर और झांसी को इस परिसर का हिस्सा बनाया जाएगा जो इस बात पर निर्भर करेगा कि चीते इस क्षेत्र का किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं।

स्टार रेटिंग के आधार पर सफाई कर्मियों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि

मुख्यमंत्री डा . यादव ने की घोषणा, स्वच्छता पखवाड़े का किया शुभारंभ

भोपाल। *मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों को स्वच्छता सर्वेक्षण -2024 में कचरा-मुक्त शहर स्टार प्रमाणीकरण में मिली स्टार रेटिंग के आधार पर कार्यरत सफाईकर्मियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जिस निकाय को जितने स्टार प्राप्त होंगे, उसमें कार्यरत सफाई मित्रों को उतने हजार की राशि दी जाएगी। एक स्टार से लेकर सात स्टार तक रेटिंग होगी। यानी एक स्टार तो एक- एक हजार रुपये और सात स्टार मिले तो सात-सात हजार रुपये प्रत्येक निकाय कर्मी को दी जाएगी।*

यह घोषणा मंगलवार को मुख्यमंत्री डा मोहन यादव ने प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी सफाई कर्मियों के आभारी हैं। मुख्यमंत्री डा. यादव एवं राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में आयोजित ÷स्वच्छता ही सेवा÷ पखवाड़े कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2024 और प्रदेश के 50 जिला चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश को स्वच्छता के क्षेत्र में प्राप्त पुरस्कारों पर केंद्रित प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया।

स्वच्छता सर्वेक्षण- 2023 में फाइव स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाली भोपाल नगर निगम को चार करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक से जारी की गई। यह राशि भोपाल नगर निगम के 8116 सफाई मित्रों को पांच-पांच हजार रुपये के मान से प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी। सफाई मित्रों का सम्मान कर प्रोत्साहन राशि और स्वच्छता किट का वितरित की गई। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, प्रदेशभर में रहवासी संघ बनाने की जरूरत है. ताकि जन भागीदारी के जरिए जनपदों को सुझाव और समस्याएं पता चल सके। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सहित अन्य उपस्थित थे।

एक लाख 31 हजार परिवार पीएम आवास में कर रहे प्रवेश -मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के एक लाख 31 हजार परिवार पीएम आवास आवासों में प्रवेश कर रहे हैं। प्रदेश में अब तक 36 लाख 24 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों को योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के माध्यम से आठ लाख पांच हजार से अधिक हितग्राही लाभान्वित हुए। प्रधानमंत्री मोदी चार करोड़ से अधिक व्यक्तियों को लाभान्वित कर चुके हैं, उनका संकल्प तीन करोड़ जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराना है।

राज्यपाल की अपील, जेनेरिक दवाएं ही लिखें

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने निजी डाक्टरों से भी कहा कि मरीजों के इलाज के समय उन्हें प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की जेनेरिक दवाएं ही लिखें। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्वच्छता के संस्कार देने की शुरूआत अपने घर से ही करना होगा।

जनजातीय वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार एवं वित्त पोषण के रूप में 43.39 करोड़ वितरित

भोपाल। जनजातीय कार्य विभाग के अधीन मप्र आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा तीन नई वित्तीय सहायता योजनाएं संचालित की जा रही हैं। भगवान बिरसा मुण्डा स्व-रोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना के जरिये जनजातीय वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार से जोड़कर उनके समग्र कल्याण के तेज प्रयास किये जा रहे हैं। इन तीनों योजनाओं में जनजातीय युवाओं को स्वरोजगार स्थापना व वित्त पोषण के रूप में 43 करोड़ 39 लाख 20 हजार 620 रूपये दिये जा चुके हैं।

मप्र आदिवासी वित्त एवं विकास निगम को भगवान बिरसा मुण्डा स्व-रोजगार योजना में 1000 हितग्राही वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 31 मार्च 2024 तक कुल 6 हजार 463 आवेदन मिले। इनमें से बैंकों द्वारा 1094 आवेदन मंजूर कर 904 जनजातीय बंधुओं को 33 करोड़ 70 लाख 47 हजार 620 रूपये वित्तीय सहायता दी गई। योजना में जनजातीय युवाओं को विनिर्माण गतिविधियों के लिए एक लाख से 50 लाख रूपये तथा सेवा व व्यावसायिक गतिविधियों के लिए एक लाख से 25 लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना में हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित, शेष ऋण पर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान तथा बैंक ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्षों तक मोरेटोरियम अवधि सहित निगम द्वारा वहन की जाती है। योजना में इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसका क्रियान्वयन 'समस्त पोर्टल' से किया जा रहा है। पोर्टल पर यह योजना मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से समन्वित होती है। जिलास्तर पर योजना का क्रियान्वयन सहायक आयुक्त/जिला संयोजक/शाखा प्रबंधक, मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम तथा महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों के माध्यम से किया जा रहा है। योजना में वर्ष 2024-25 के लिये सभी जिलों के बैंकों को वार्षिक लक्ष्य दे दिये गये हैं। संबंधित अधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन संबंधी निर्देश भी जारी किये गये हैं। इच्छुक व्यक्ति पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के 10 हजार हितग्राही वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध निगम को 31 मार्च 2024 तक 7 हजार 116 आवेदन मिले। बैंकों द्वारा 1130 आवेदन मंजूर कर 908 जनजातीय बंधुओं को 5 करोड़ 8 लाख रूपये से अधिक की वित्तीय सहायता दी गई। योजना में जनजातीय युवाओं को 10 हजार से एक लाख रूपए तक की स्व-रोज़गार परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। बैंक ऋण पर अधिकतम 5 वर्षों के लिए 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं बैंक गारंटी सरकार देती है। इन दोनों योजनाओं की विस्तृत जानकारी एवं लाभ प्राप्ति के लिए समस्त पोर्टल पर लॉग-इन कर या जिलास्तर पर सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना में जनजातीय युवाओं की आजीविका, स्व-रोजगार एवं सामुदायिक अधोसंरचना निर्माण तथा इनसे जुड़ी अन्य गतिविधियों की दो करोड़ रूपये तक की ऐसी परियोजनाएं, जिनका क्रियान्वयन लाईन विभागों की किसी प्रचलित योजना/परियोजना में करना संभव न हो उसका शत-प्रतिशत वित्त पोषण किया जाता है।

मुख्यमंत्री लगवा रहे हर लाड़ली बहना के घर फोन

फिर शुरू होंगे खाते, हर माह मिलेगी 1250 रुपए की किश्त

भोपाल। प्रदेशभर की लाड़ली बहनाओं को हर माह मिल रही 1250 रुपए की किश्त के साथ एक नई पहल की गई, जिसमें गलती से महिलाएं लाड़ली बहना की किश्त को नामंजूर कर रही थीं, लेकिन बढ़ती सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को देखते हुए सीएम हेल्पलाइन द्वारा हर लाड़ली बहना के घर फोन लगाकर इस बात की जानकारी ली जा रही है कि उन्होंने लाड़ली बहना की राशि लेना नामंजूर किया है। इस पर महिलाओं ने बताया कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं चाहा। संभव है कि कम्प्यूटर आपरेटर की गलती के कारण उनसे हक त्याग हो गया हो। पता चला है कि प्रदेश में हजारों महिलाओं ने लाड़ली बहना की किश्त की राशि अस्वीकार कर दी।

पुलिसकर्मियों की सैलरी से कटेंगे 30 रुपए

भोपाल। मप्र के डेढ़ लाख से अधिक जवान और अधिकारियों की सैलरी से 30 रुपए काटे जाएंगे। पीएचक्यू ने कारपस निधि की रकम बढ़ाकर 50 कर दी है। जिसके बाद यह रकम अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को भेजी जाएगी। डीजीपी सुधीर सक्सेना की अनुमति के बाद वेलफेयर विंग ने आदेश जारी कर दिया है। वेलफेयर शाखा के एआईजी डॉ. अंशुमान अग्रवाल ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं।

आदेश के मुताबिक, वित्तीय वर्ष अप्रैल 2024 से अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड नई दिल्ली को कारपस निधि में वार्षिक अनुदान की राशि 20 रूपए से बढ़ाकर 50 रूपए प्रति अधिकारी-कर्मचारी के मान से भेजने हेतु सहमति व्यक्त की गई है, जोकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में रुपये 20 के मान से प्राप्त हुई है। अत- 20 रूपए से बढ़ाकर 50 रूपए प्रत्येक अधिकार-कर्मचारी के मान से कारपस निधि की राशि बढ़ाये जाने के कारण वित्तीय वर्ष 2023-24 की अंतर की राशि 30 रूपए के मान से माह सितम्बर 2024 के वेतन से कटौत्रा किया जाकर आवश्यक रूप से माह अक्टूबर 2024 में ही भेजने का कष्ट करें। वित्तीय वर्ष 2024-25 से प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के वेतन से 50 रूपए के मान से कारपस फण्ड की नियमित रूप से वार्षिक अंशदान कटौत्रा के साथ माह सितंबर 2024 के वेतन से कटौत्रा करने के निर्देश जारी किये जाते हैं। यह निर्देश आगामी आदेश पर्यन्त तक जारी रहेगा।

BOLLYWOOD UPDATE

खुद को हेल्पलेस महसूस करती है अनन्या पांडे

इन दिनों अपनी पहली वेब सीरीज 'कॉल मी बे' को लेकर खबरों में छाई अनन्या पांडे के दमदार अभिनय की खूब तारीफ हो रही है। हाल ही में अनन्या ने एक इवेंट में हिस्सा लिया। इसी दौरान अनन्या ने मी टू मूवमेंट के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि इस मूवमेंट ने उनपर गहरा असर डाला और एक्ट्रेस होने के नाते कभी-कभी वो खुद को बहुत हेल्पलेस महसूस करती हैं। इवेंट के दौरान एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए उन्हें संवेदनशील मुद्दों पर ज्यादा न बोलने की सलाह दी जाती है। उन्होंने कहा कि वे अपने काम के जरिए इंडस्ट्री में बदलाव लाने की कोशिश करेंगी। अनन्या की सीरीज में महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दे को उठाया गया है। सीरीज में मी टू मूवमेंट से जूझ रही महिलाओं की कहानी दिखाई गई है। इसके बारे में बात करते

हुए अनन्या ने कहा, 'मैं आपको सीरीज की कहानी नहीं बताना चाहती, लेकिन 'कॉल मी बे' काफी हद तक महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मैं कई वजहों से खुलकर नहीं बोल पाई, लेकिन मैं अपनी फिल्मों के जरिए कुछ बदलाव लाना चाहती हूं। अनन्या ने फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की सुरक्षा पर बात करते हुए कहा, हर इंडस्ट्री के लिए हेमा कमेटी जैसी एक कमेटी होना बेहद जरूरी है, जहां महिलाएं एकजुट होकर कुछ पॉजिटिव पहल करें। साफ है कि ऐसा कदम सिर्फ महिलाएं ही उठा सकती हैं।

ओटीटी की क्वीन मानी जाती है आभा पॉल

ओटीटी प्लेटफॉर्म की बोल्ड वेब सीरीज की बात जब भी आती है तो आभा पॉल का नाम सबसे ऊपर आता है। 'मस्तराम' और 'गंदी बात' समेत कई एडल्ट वेब सीरीज में अपनी बोल्डनेस का तड़का लगाने वालीं आभा अपनी हॉट फोटोज को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं। उनके हुस्न का जलवा देखने के लिए उनके फैंस भी काफी बेकरार रहते हैं। जाहिर है कि एक्ट्रेस का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड तस्वीरों से भरा पड़ा है।

आभा पॉल

आपको बता दें कि आभा पॉल साउथ फिल्म इंडस्ट्री

का जाना-माना चेहरा हैं। उन्हें अब तक कई फिल्मों में देखा जा चुका है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की रहने वालीं आभा को असली पहचान ओटीटी प्लेटफॉर्म से मिली है। उन्होंने ऑल्ट बालाजी की कई वेब सीरीज में काम कर पॉपुलैरिटी बटोरी है।

बता दें कि एक्ट्रेस आभा पॉल अपने सिजलिंग लुक से अक्सर कहर ढाती हैं। यूं तो एक्ट्रेस वेस्टर्न लुक में अपने किलर पोज से फैंस को सरप्राइज कर देती हैं लेकिन इस बार इंडियन लुक में उन्होंने तस्वीरें शेयर करते हुए फैंस का दिल खुश कर दिया है।

लगातार गलत मुद्रा में बैठना सेहत के लिए ठीक नहीं है। इससे कई तरह की शारीरिक समस्याएं होने का खतरा रहता है वहीं, सही मुद्रा में बैठने से शरीर को कई तरह से फायदा होता है।

सही मुद्रा में बैठने से शरीर को कई फायदे

ग़लत मुद्रा में बैठने का सबसे ज्यादा बुरा असर रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है। गलत मुद्रा में कुर्सी पर बैठने, उठने या झुककर गाड़ी चलाने के कारण पीठ में दर्द की समस्या हो जाती है। यह स्थिति रीढ़ की हड्डी को ज्यादा देर तक सीधा न रखने के कारण पैदा होती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि झुककर नहीं, अपनी पीठ सीधे रखकर बैठो। रीढ़ की हड्डी का दर्द शरीर के दूसरे अंगों तक भी फैल सकता है, जैसे कंधे, बाजू, पीठ का निचला हिस्सा, कूल्हे, टांग और पैर भी। सही मुद्रा में बैठने से शरीर को कई तरह से फायदा होता है।

सिर दर्द से छुटकारा : बार-बार सिरदर्द होने के कई कारण हो सकते हैं जैसे माइग्रेन, सामान्य सर्दी या अच्छी नींद न होना। लेकिन सिरदर्द का एक सबसे आम कारण है गलत पॉश्चर में बैठना। कंधे झुकाकर बैठने से गर्दन के पीछे खिंचाव होता है। बैठने का पॉश्चर सही करने से सिरदर्द की शिकायत कम करने में मदद मिलती है।

अधिक ऊर्जा : जब बैठते समय रीढ़ सीधी होती है तो पीठ की मांसपेशियां अधिक अलाइन्ड होती हैं। यह भी उन्हें अधिक गतिशीलता देता है। बैठने का खराब पॉश्चर मांसपेशियों की गति को बाधित करता है। इसका मतलब है कि रीढ़ को गतिशील रखने के लिए मांसपेशियों को अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। इसलिए बहुत सारी ऊर्जा इन मांसपेशियों द्वारा उपयोग की जाएगी और यह थका हुआ महसूस करा सकता है।

बढ़ती है फेफड़ों की क्षमता : यदि व्यक्ति आगे की तरफ झुककर बैठता है तो उसके दोनों फेफड़े संकुचित होते हैं और उथली सांस लेते हैं। लेकिन एक सही मुद्रा में बैठना फेफड़ों को पूर्ण रूप से फैलने देता है। इससे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। सीधे बैठना ब्रोन्कियल समस्याओं वाले लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

बेहतर रक्त संचार : जब कंधे झुकाकर बैठते हैं, तो आपका पूरा शरीर ऊपर की ओर झुका होता है। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है। अच्छा पॉश्चर रक्त वाहिकाओं को खुला व मुक्त रखता है और रक्त को सहजता से बहने देता है। यह आपके शरीर के अंगों को पोषण देता है।

पीठ दर्द नहीं

ऑफिस में लंबे समय तक बैठकर काम करने वाले पीठ सीधी न रखकर अगर आगे झुककर बैठते हैं तो रीढ़ की हड्डी में अपनी डिस्क और लिगामेंट्स पर अनुचित दबाव डालते हैं। इसीलिए अगर आप लंबे समय से बैठे हैं तो अक्सर कमर दर्द का अनुभव हो सकता है। अगर ऐसे पॉश्चर जारी रहता है, तो पीठ का दर्द गंभीर हो सकता है। इसे ठीक करने के लिए, आपको सीधे बैठने की जरूरत है, ताकि आपकी मांसपेशियां और लिगामेंट्स आपकी रीढ़ को सपोर्ट करें और रीढ़ पर एक समान भार पड़े।

स्वस्थ रहेंगे जोड़

बैठने का सही पॉश्चर यह सुनिश्चित करता है कि रीढ़ की हड्डी स्वस्थ रहे। स्पाइनल डिस्क एक जेली जैसी संरचनाएं हैं जो रीढ़ को झटके से बचाती हैं और इसे गतिशीलता प्रदान करती हैं। जब ये डिस्क स्वस्थ होती हैं, तो जोड़ों यानी जॉइन्ट्स में दिक्कत नहीं होती है जो कि गंभीर पीठ दर्द का एक आम कारण होता है।

ज्यादा ताकत

सही मुद्रा ऊपरी शरीर की ताकत को बढ़ाती है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि यह आसन ऊपरी पीठ की मांसपेशियों और कंधे की मांसपेशियों को मजबूत और सक्रिय रखता है। जब व्यक्ति बैठता है, तो उसे अपने पॉश्चर के प्रति सचेत होना चाहिए। फिर सीधे बैठने के लिए प्रयास की जरूरत नहीं होगी, यह स्वाभाविक रूप से होगा।

काम की बातें

एक टीके से कैंसर वाले संक्रमण से छुटकारा

नए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) वैक्सीन के सिर्फ एक टीके से कैंसर के लिए जिम्मेदार वायरस के संक्रमण से छुटकारा मिल सकता है। यह दावा एक हालिया शोध में किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के हेल्थ साइंस सेंटर द्वारा किए गए इस शोध के मुताबिक, एचपीवी वैक्सीन का एक टीका इस वायरस से होने वाले संक्रमण को खत्म करने में वर्तमान समय में दी जाने वाली तीन खुराक की सीरीज के जितना ही प्रभावी है। हालांकि, यह शोध अभी सिर्फ महिलाओं पर किया गया है। इस शोध में यह भी दावा किया गया है कि नया एचपीवी वैक्सीन लगभग 90 फीसदी कैंसर पैदा करने वाले एचपीवी संक्रमणों से रक्षा करने में सक्षम है। शोधकर्ता ने कहा कि अगर एक खुराक वाले इस नए टीके का क्लीनिकल ट्रायल सफल रहता है तो वैश्विक स्तर पर कैंसर से जंग में मदद मिलेगी।

बच्चों की सेहत के लिए खतरा हैं चीनी खिलौने

चीन में बने सस्ते खिलौनों ने दुनियाभर के बाजार पर अपना कब्जा जमाया हुआ है, लेकिन यह बच्चों की सेहत पर बहुत भारी पड़ रहा है। एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि चीनी खिलौनों से बच्चों के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। इस अध्ययन में कहा गया है कि इन खिलौनों को बनाने के लिए खतरनाक धातुओं समेत बेहद घातक चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। यह शोध केंद्र सरकार और भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) ने किया है। अध्ययन के मुताबिक, चीन द्वारा निर्मित अधिकांश खिलौने भारतीय सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे और इन्हें बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदेह बताया गया। अब इन खिलौनों को बिक्री के लिए भारतीय बाजारों में प्रवेश की अनुमति देने से पहले, प्रत्येक कंटेनर से नमूने लेकर जांच होगी।

यह भी जानें यूरिन संबंधी बीमारियों को डॉक्टरों की भाषा में यूरिनरी ट्रेक्ट इन्फेक्शन्स कहा जाता है, मांसाहारियों में इसकी संभावना अधिक होती है

यूरिन इन्फेक्शन से बचना है तो अपनाएं शाकाहारी भोजन

यूरिन इन्फेक्शन यानी पेशाब संबंधी बीमारी आम समस्या है। उम्र के साथ यह समस्या बढ़ती जाती है। महिलाओं को इससे ज्यादा जूझना पड़ता है। अब इस समस्या से जुड़ा एक रोचक अध्ययन सामने आया है। इसके मुताबिक, जो लोग शाकाहारी भोजन करते हैं, उनमें यूरिन इन्फेक्शन की आशंका कम होती है। यूरिन संबंधी बीमारियों को डॉक्टरों की भाषा में यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रेक्ट इन्फेक्शन्स कहा जाता है। यूटीआई आमतौर पर ई. कोलाई जैसे आंत बैक्टीरिया के कारण होता है, जो मूत्रमार्ग में प्रवेश करते हैं। ये न केवल मूत्राशय, बल्कि गुर्दे को भी प्रभावित करते हैं। ताइवान में बौद्ध टीजू ची मेडिकल फाउंडेशन का यह अध्ययन जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ताओं ने पाया कि मांसाहारियों की तुलना में शाकाहारियों में यूटीआई का जोखिम 16 प्रतिशत कम था।

पोल्ट्री और सूअर के मांस को ई. कोलाई का स्रोत माना गया है तथा इसी ई. कोलाई के कारण यूरिन का इन्फेक्शन होता है। शाकाहारी लोग इन खाद्य पदार्थों से दूर रहते हैं, इसलिए ई. कोलाई से भी बचे रहते हैं। बच्चों की तुलना में वयस्कों में यह बीमारी अधिक होती है। वहीं पुरुषों की तुलना में महिलाओं और लड़कियों में इसकी आशंका अधिक रहती है। हालांकि, इसके पीछे का कोई स्पष्ट कारण नहीं है, लेकिन अंगों की बनावट को इसका कारण माना जा सकता है। बार-बार पेशाब आना, पेशाब करते समय जलन होना, पेशाब में खून आना, पेशाब करते समय पेट के निचले हिस्से में जलन होना इसके सामान्य लक्षण हैं। यूरिन इन्फेक्शन के कई कारण हो सकते हैं जैसे- असुरक्षित यौन संबंध, अस्वच्छ रहने की आदत, पथरी, गर्भावस्था, एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक प्रयोग, मूत्राशय को पूरी तरह खाली न कर पाना आदि। साथ ही डायबिटीज, मोटापा, गर्भावस्था और आनुवंशिकता भी यूरिन इंफेक्शन का कारण बन सकते हैं। पुरुषों में डायबिटीज या प्रोस्टेट के बढ़ने के कारण यूरिन इन्फेक्शन होता है।

साफ सफाई का ध्यान रखें

गुप्तांग शरीर का संवेदनशील हिस्सा होता है। साथ ही इनमें बाहरी संक्रमण का खतरा भी अधिक होता है। यदि यूरिन पास होने वाली ट्यूब यानी यूरेथरा की सही तरीके से सफाई न की जाए तो संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। कई मामलों में यह संक्रमण ब्लॉडर तक पहुंच सकता है। ब्लॉडर में सूजन जैसी समस्या भी देखने को मिलती है। सलाह दी जाती है कि बाथटब के बजाय शॉवर या बाल्टी से नहाएं। बाथटब के कारण यह इन्फेक्शन फैल सकता है। यौन संबंध से पहले और बाद में साफ सफाई का ध्यान रखें। जिन लोगों में पथरी की शिकायत रहती है या किसी कारण से मूत्र मार्ग की सर्जरी हुई है, उन्हें विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए।

जस्टिस सुरेश कुमार कैत एमपी हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे

इन्दौर। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा जस्टिस सुरेश कुमार कैत को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस अप्वाइंट करने के साथ ही 7 प्रदेशो की हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अप्वाइंट्स किए। सुप्रीमकोर्ट कोलेजियम द्वारा पूर्व में चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंटमेंट हेतु कुछ नामो की अनुशंसा में भी परिवर्तन किया है। एस सी कैटेगरी के जस्टिस सुरेश कुमार देश के हाईकोर्ट जजेज की वरिष्ठता के क्रम के 5 वे क्रम पर है और 23 मई 2025 को आपका रिटायरमेंट है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित 11 जुलाई के अपने प्रस्ताव में मंगलवार को बदलाव किया। खबर है कि सरकार की तरफ से मिली संवेदनशील जानकारी में खास बात देखते हुए कॉलेजियम ने फैसले पर दोबारा विचार किया है। दिल्ली

उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति कैत की पहले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की गई थी। अब उन्हें मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति संधावालिया को पहले मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी। अब उन्हें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई है।

न्यायमूर्ति ताशी राबस्तान को मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई थी। कॉलेजियम ने अब उन्हें जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने कहा कि वर्तमान प्रस्ताव 11 जुलाई को न्यायमूर्ति मनमोहन, न्यायमूर्ति राजीव शकधर, न्यायमूर्ति नितिन मधुकर जामदार और न्यायमूर्ति के आर श्रीराम के संबंध में की गई सिफारिशों को प्रभावित नहीं करेगा। बीते सप्ताह ही अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच को बताया था की 7 उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी को सही ठहराने के लिए उनके पास कुछ सामग्री है। उनका कहना था कि सामग्री संवेदनशील है और सीलबंद लिफाफे में रखने की बात कही थी। सीजेआई यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले कॉलेजियम में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई भी शामिल हैं। उन्होंने पूर्व में की गई कई अपनी सिफारिशों में बदलाव किए हैं।

कॉलेजियम ने सात उच्च न्यायालयों दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, केरल, मध्यप्रदेश, मद्रास और मेघालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश की थी। इस बीच, कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत, न्यायमूर्ति जी एस संधावालिया और न्यायमूर्ति ताशी राबस्तान की नियुक्ति के संबंध में अपनी सिफारिशों में बदलाव करने का निर्णय लिया।

आर्थिक तंगी दूर करने के लिए नए मार्केट बनाएगा निगम

पुरानी दुकानों का भी किया जाएगा मेंटेनेंस, होगा रंगरोगन

इंदौर। लगातार आर्थिक संकट झेल रहा नगर निगम तंगहाली दूर करने के लिए नए रास्ते खोज रहा है। इसी के तहत निगम अब शहर में खाली पड़ी जमीनों पर ऐसे मार्केट बनाने की तैयारी कर रहा है जिससे उसे लगातार प्राप्त होती रहे। साथ ही इन मार्केट में दुकान आदि किराए पर देने पर भी एक मूत्र राशि अमानत के तौर पर प्राप्त हो सके। इस धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों में निगम कर सके। न सिर्फ नए मार्केट बनाने की तैयारी की जा रही है बल्कि निगम अपने पुराने मार्केट अर्थात दुकानों और अन्य स्थानों को मेंटेनेंस करने की भी तैयारी कर रहा है। इनका सुधार करवा कर रंग रोगन इत्यादि करवाया जाएगा, जिससे नए प्रतीत हों।

अधिकारियों के अनुसार लगातार चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि शासन स्तर से काटे जाने के कारण निगम आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। यह लगातार कई महीनो से जारी है। हालात यहां तक हो गए हैं कि भुगतान नहीं होने के कारण निगम का कार्य करने में ठेकेदार भी रुचि नहीं दिख रहे हैं। ऐसे हाल तो से निपटने के लिए निगम अब स्थाई आने वाले साधन तलाश कर रहा है। इनमें सबसे पहले ऐसे मार्केट और दुकानों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है जिसे निगम को लगातार किराया प्राप्त होता है। इसी दुकानों को बनाने के लिए निगम शहर में और शहरी सीमा पर खाली जमीन की तलाश कर रहा है। बताया जा रहा है कि निगम अधिकारियों ने इसके लिए टीम बनाकर झोन स्तर पर सर्वे भी शुरू कर दिया है। सूत्र बताते हैं कि प्रत्येक झोनल कार्यालय को यह निर्देश दिया है कि वह अपने क्षेत्र में ऐसे स्थान का सर्व करें जहां पर मार्केट और दुकानें बनाने से निगम को बेहतर आय प्राप्त हो सके।

पुरानी दुकानों की भी हालत सुधारने पर दे रहे ध्यान

जानकारी अनुसार नगर निगम अपनी पुरानी दुकान जिन मार्केट में स्थित है वहां मेंटेनेंस का कार्य भी शुरू करने की तैयारी में है। हालांकि आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे निगम को सुधार कार्य के लिए ठेकेदारों की परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके बाद भी निगम पुराने मार्केट का मेंटेनेंस करवा कर नए जैसे बनाने की हर कोशिश कर रहा है।

मप्र कांग्रेस के नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी

इंदौर। देश की चार राज्य जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही है। अखिल भारती कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) मध्य प्रदेश के नेताओं को भी इन चार राज्यों में जिम्मेदारी सौंप रही है। खास बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इन चुनावो में मध्य प्रदेश के युवा नेताओं, पूर्व विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। इनमें प्रमुख रूप से कुणाल चौधरी को महाराष्ट्र विदर्भ की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पूर्व विधायक पीसी शर्मा को भी महाराष्ट्र की जिम्मेदारी की दी गई है। पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े को महाराष्ट्र भेजा गया है। जबकि युवा और आदिवासी नेता डॉ. विक्रांत भूरिया को झारखंड की जिम्मेदारी सौंप गई है। वहीं युवा नेता और प्रदेश प्रवक्ता अब्बास हाफिज को जम्मू कश्मीर में जिम्मेदारी सौंप गई है। जबकि चित्रकूट के पूर्व विधायक नीलांशु चतुर्वेदी को हरियाणा भेजा गया है। मध्य प्रदेश में एक समय था जब यहां के बड़े दिग्गज नेताओं को दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी दी जाती थी, लेकिन कुछ समय से प्रदेश के युवा नेतृत्व पर विश्वास किया जा रहा है। एआईसीसी इससे पहले सीनियर नेता कमलनाथ से प्रदेश की कमान लेकर युवा नेता जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। वहीं अब दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी बड़े नेताओं की जगह युवा और अपनी अलग पहचान रखने वाले नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। युवा नेताओं को दूसरे राज्यों में प्रचार प्रसार के लिए भेजा जा रहा है। जानकारी के अनुसार कुछ और युवा नेताओं को चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भेजा जा सकता है। हालांकि कुछ सीनियर नेताओं को भी जिम्मेदारी दी जा रही है।

विक्रांत भूरिया को आदिवासी वोट साधने की जिम्मेदारी-मध्य प्रदेश के युवा और आदिवासी नेता डॉ विक्रांत भूरिया को झारखंड की जिम्मेदारी सौंप गई है। झारखंड में आदिवासियों का वोट ज्यादा है। यही वजह है कि उन्हें झारखंड भेजा गया है। पिछले चुनाव में आदिवासी वोटरों की वजह से ही बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ा था।

स्वच्छता ही सेवा के तहत सफाई मित्रों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित

इंदौर। *स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत इंदौर रेलवे स्टेशन पर सफाई मित्र सुरक्षा शिविर और हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। सिर्फ इंदौर ही नहीं रतलाम मंडल के 10 अन्य लोकेशनों पर भी यह सिविल लगाए गए। इसमें सफाई मित्रों के स्वास्थ्य की जांच की गई।*

रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीना ने बताया कि इस अभियान के तहत रतलाम मंडल के नागदा, नीमच, रतलाम स्टेशन, रतलाम स्वास्थ्य निरीक्षक कार्यालय, डॉ, अम्बेडकर नगर, चित्तौड़गढ़, मंडल चिकित्सालय रतलाम, इंदौर हेल्थ यूनिट , उज्जैन रेलवे स्टेशन में सफाई मित्र सुरक्षा शिविर एवं हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान सफाई मित्रों की स्वास्थ्य जांच कर सुरक्षा गियर/किट का वितरण किया गया। शिविर के दौरान सफाई मित्रों को कार्य के दौरान स्वयं की सुरक्षा संबंधी उपयों, सुगम स्वास्थ्य सुविधाएँ एवं सामाजिक कल्याण की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। इस अभियान के तहत 228 से अधिक सफाई मित्रों की स्वास्थ्य परीक्षण किया गया एवं सुरक्षा गियर/किट का वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त मंडल के विभिन्न लोकेशनों पर चिह्नित किए ब्लैक स्पॉट की सफाई करवाई गई।

प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी जयश्री जैन द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स 13, प्रेस कॉम्प्लेक्स ए.बी. रोड इंदौर से मुद्रित एवं 22, प्रेस काम्पलेक्स, प्रेस हाऊस, ए.बी. रोड इंदौर 452008 से प्रकाशित। प्रधान संपादक- डॉ. राजेश जैन, मो. 9425322301 (डाक पंजीयन MP/IDC/1462/2016-2019)